

वना है। एक्सीडेंट्स का सबाल पूछा नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। कुल 64 शिकायतें आईं। उन में से 49 केमिस्ट ऐसे थे जो सबस्टेंशिएट नहीं हुए, गलत थे, साबित नहीं हुए। 7 की इनक्वायरी हो रही है। 8 में सेंटेंस हो चुकी है। इतने बड़े शहर में कुल 64 एक्सीडेंट्स हुए तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि यह तशबीहनाक मिचुगशन है।

श्री एस० रामगोपाल रेड्डी : अभी मंत्री जी ने कहा कि एक्सीडेंट्स कम हो गये हैं तो क्या उनमें कुछ ज्यादा करने की गुंजाइश रखी गई है ?

बहुत भी पार्लिमेन्टल पार्टीज ऐसी हैं जिनमें ज्यादातर डेथम पार्टी में है तो क्या वह लोग भी बाटलनेक्स क्रिएट करने दें ?
(व्यवधान) ..

MR. SPEAKER: No, it does not arise out of this

श्री हुकम चन्द कछवाय : दिल्ली में जो यातायात की समस्या है वह देश के सभी महानगरों, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर में भी है।

MR. SPEAKER: We are on Delhi only.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यातायात की इन कठिनाइयों के कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन के हल करने के बारे में क्या किया जा रहा है ? एक्सीडेंट्स कम-से-कम होने सम्बन्धी नियमों का पालन सभी महानगरों में ठीक प्रकार से नहीं होता है। दिल्ली में तो फिर भी कुछ लोग इन नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अभी हाल में जो पैट्रोल के दाम बढ़े हैं, इस विषय को लेकर जो टैक्सी और स्कूटर वाले हैं, वह प्रायः यात्रियों

में झगड़ा करते हैं और ज्यादा किराय वसूल करते हैं। बाहर में जो अपने वाहनों यात्री होते हैं, उनमें रेलवे स्टेशन पर मुह मागे पैसों देने के लिए जब यात्री तैयार हो जाता है तो उसको मबारी में बिठाया जाता है। (व्यवधान) क्या इस तरह व कोई कदम उठाया जायेगा कि यात्रियों को अधिक किराया न लिया जा सके और एक्सीडेंट्स भी न हों ? (व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is a totally different question.

Concessions to Cement Manufacture

*411 **SHRI AHMED M. PATI**
Will the Minister of INDUSTRY
pleased to state:

(a) whether Government are considering to offer certain concessions to the indigenous cement manufacturers for increasing the cement production

(b) if so, the details of such concessions; and

(c) the reaction of the cement manufacturers?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES):
to (c). Government are actively considering the appointment of a high level committee for carrying out a comprehensive review of the cement industry. The terms of reference to the proposed committee would include including the question of long-term measures for encouraging the creation of additional capacity. Government are also considering certain proposals for short-term incentives to encourage additional production out of the existing capacity. These proposals are to be finalised.

श्री अहमद एम० पटेल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह हा लैबल कमेटी कब तक बन जायेगी और उ प्रपोजल मंत्री जी ने बताया है, वह कब त फाइनल हो जायेगा ?

श्री जार्ज कर्नलिस : अध्यक्ष दय, यह कमेटी अगले 4, 6 सप्ताहों के भीतर बननी चाहिए, जिसमें इस उद्योग सम्बंधित तमाम मंत्रालय और इस ग के प्रतिनिधि शामिल किये जायेंगे और सीमेंट उद्योग के बारे में विचार कर के, एक कर उत्पादन को कैसे बढ़ाया, दाम बढ़ाए की समस्या को प्रकाश में हल किया जाय, नये खान लगात समय अभी जा बहुत क पत्ती की जरूरत है, उस समस्या को हल किया जाये, उन सारे ममाला पर कमेटी अपनी राय देने का काम करेगी।

जहां तक तात्कालिक समस्याएं दूर न का सबाल है, उसमें हम अगले कुछ दिनों के भीतर निर्णय कर लेंगे। उस में यह सोच रहे हैं कि बिजली का बड़ा रिया है कई जगह पर सीमेंट का उत्पादन बिजली की कमी के कारण ज़रूरत में चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। सीमेंट कारखाना को कह रहे हैं कि वह ठीक प्लांट लगावें, उसमें कुछ छूट देने बात हम सोच रहे हैं, पर निर्णय अभी किया गया है।

उसी तरह से स्लैब और पाजेलैटिक एट निर्माण करने के बारे में सीमेंट खानों को कह चुके हैं, कुछ लॉग काम में है मगर उसमें कुछ दिक्कतें हैं। जहां अधिक मदद की जरूरत पड़ेगी, उस भी इस समय सोच रहे हैं और कुछ समय इस पर निर्णय ले पायेंगे।

मिनी सीमेंट प्लाण्ट लगाने के बारे में कुछ रियायतें देने का काम भी हम कर रहे हैं।

HRI VAYALAR RAVI: He cannot make a policy statement during the session hour.

MR. SPEAKER: Yes, he has already made a policy statement earlier.

HRI GEORGE FERNANDES: I am not making any policy statement.

I am only saying there are the various areas where immediate relief is being contemplated and it will take probably a few days to announce the relief.

श्री अहमद एम० पटेल : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि वे प्रोपोज़ल्ज़ फ़ाइनलाइज़ हो जाने के बाद सीमेंट की तृणी सम्पूर्ण तौर पर ख़तम हो जायेगी ?

श्री जार्ज कर्नलिस : सीमेंट की तृणी को दूर करने में तो हमें कुछ समय लग जायेगा। इस समय हमारी कैपेसिटी मुश्किल से 22 मिलियन टन है, और हमारी आवश्यकता उस में ज्यादा है। अपने पांच वर्षों में लगभग 15 मिलियन टन और सीमेंट की कैपेसिटी बढ़ाने की योजना इस समय कार्यान्वित हो रही है। मगर वे नये कारखाने खड़े होने में समय लग जायेगा। दरमियान के समय में सीमेंट की कमी का पूर्य करने के लिए हम सीमेंट का आयात कर रहे हैं।

श्री छवि राम अग्रवाल : सीमेंट मिमांता सीमेंट में मिलावट करने है, जिस में लोगों का घटिया किस्म का सीमेंट मिल रहा है। सीमेंट में ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहा है—एक एक बैग चासीस चासीस रुपये में मिल रहा है। ग्रामीण अंचलों में सीमेंट उपलब्ध नहीं है। अधिकांश सीमेंट की खपत शहरों में हो जाती है। क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि ग्रामीण अंचलों में किसानों को उन की आवश्यकता के मुताबिक सीमेंट उपलब्ध हो ?

श्री जार्ज कर्नलिस : जहां तक सीमेंट बेचने का प्रश्न है, वह काम कम्पनियों अपने डीलरों के माध्यम से करती हैं। लगभग 24,000 डीलरों सारे देश में है। एलाटमेंट करने का काम हर राज्य करता है। अगर मिलावट के बारे में कोई ठोस शिकायत हो, तो उस की जांच

करने के बारे में जो कदम उठाना चाहिए, वह हम अपनी तरफ से उठावेंगे। गांवों में सीमेंट पहुंचाने के लिए हम राज्य सरकारों को कहेंगे कि जहां भी इस प्रकार की शिकायत हो, उसे वे दूर करें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, चूंकि हम कभी को आयात में पूरा करने के काम में लगे हुए हैं, इस लिए, जिस किसी क्षेत्र में सीमेंट के बारे में कुछ परेशानी नजर आती है, वह अगले चन्द दिनों में हम दूर कर देंगे। हम राज्य सरकारों को कह देंगे कि वे गांवों तक सीमेंट पहुंचावें। मैं राज्य सरकारों से कह सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं पहुंचा सकता हूँ।

SHRI R. VENKATARAMAN: The hon. Minister is aware that experiments have been carried out in small-scale cement plants. The Government of India have actually taken over a cement plant in Tamil Nadu at Ariyalur and have worked on it. May I know whether the terms of reference of this Committee will include an examination of the feasibility as well as the problems of the small-scale cement plants, along with those of the large-scale plants?

SHRI GEORGE FERNANDES: No, Sir. It is not proposed to make this Committee discuss the mini cement plants or the small-scale cement plants and the problems pertaining to this sector. We have a few mini cement plants currently in operation. More are being contemplated. Plants with a capacity up to 100 tonnes are being to be treated as mini cement plants. Our effort is to encourage the installation of as many of these as possible in the coming few months.

Basis for distribution of Imported T.V. Picture Tubes

*412. **SHRI P. K. KODIYAN:** Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) whether the basis of distributing the imported TV picture tubes

has been shifted from licensed capacity to production capacity since last year;

(b) if so, the details thereof and reasons therefor;

(c) whether Government are aware that this shift in policy has put the small electronic industry in trouble; and

(d) if so, the details thereof and whether the same policy which prevailed earlier will be restored?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

SHRI P. K. KODIYAN: I am surprised to hear this "No, Sir" answer. Here the question is about the distribution of imported T.V. picture tubes. As a result of the policy of the Government of encouraging particular units which have got more influence to get more picture tubes, a number of small units which produce T.V. sets have already been forced to close down, and yet the hon. Prime Minister says that the policy has not changed. May I ask the Prime Minister how was it that some units whose licensed capacity was 20,000 maximum, were able to produce as much as 40,000 TV sets? I want to know how this has happened?

SHRI MORARJI DESAI: There is no question of change in policy now. This was done in order to see that only the bigger producers do not get all the advantage. So, it was distributed equitably to all and that is being followed. The smaller units are doing better, that is a good thing and not a bad thing.

SHRI P. K. KODIYAN: Is there any proposal on the part of the Government to have production of these TV picture tubes in our own country? And to attain self-sufficiency in this matter or in order to reduce to the maximum